


आदेश पत्रक - ता०.....से.....तक
जिला....., सं०....., सन् १९.....
केस का प्रकार.....

<p>आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १</p>	<p>आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २</p>	<p>आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३</p>
	<p style="text-align: center;">न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा</p> <p style="text-align: center;">भूमि विवाद अपील वाद संख्या: ११/२०१२</p> <p style="text-align: center;">जोगी मंडल एवं अन्य — अपीलार्थीगण बनाम राज्य एवं अन्य — रेस्पोण्डेन्ट्स</p> <p style="text-align: center;">-:आदेश:-</p> <p>प्रस्तुत अपील वाद जोगी मंडल द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, निर्मली, सुपौल द्वारा पारित आदेश दिनांक: ०६.०२.२०१२ई० अन्तर भूमि विवाद वाद संख्या: ४२/२०११-१२ के विरुद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट्स दायर किया गया है।</p> <p>वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया।</p> <p>प्रस्तुत अपील वाद में मौजा: हरियाही खाता: ८४ एवं ५५ खेसरा २६१८, २६२१, २६४१, २६४२, ३१५२, ३२३७, २४७१ एवं २७८१ एवं अन्य खेसरा का कुल रकबा ६-१८-११-१० (छ: बीघा अठारह कट्ठा ग्यारह धूर दस धूरकी) तथा खाता ७५ खेसरा २८२८ का रकबा ०.९.१६ (नौ कट्ठा सोलह धूर) भूमि विवादित भूमि है।</p> <p>अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि उक्त विवादित जमीन उभय पक्ष के पूर्वजों की अर्जित सम्पत्ति है। उनके दखल कब्जा के आधार पर सम्मिलित जमाबंदी संख्या ५५ भूतपूर्व जमीन्दार महाराज दरभंगा के समय से तथा कालान्तर में बिहार सरकार को राजस्व का भुगतान किया जाता रहा है वो वर्ष: १९०५ से पूर्व ही दोनों पक्षों का स्वतंत्र हैसियत कायम हुआ तथा व्यक्तिगत हैसियत से जमीन की खरीदगी हुई। जिसकी जमाबंदी संख्या: १७ एवं १०४ कायम हुआ तथा पुनरीक्षित सर्वे अपीलार्थी/वादी पूर्वज के नाम से खाता खुला। उक्त जमाबंदी का संबंध साबिक खाता ७५ एवं ८४ की भूमि से रहा जिससे रेस्पोण्डेन्ट का कोई संबंध नहीं होना बतलाते हैं।</p> <p>अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि रेस्पोण्डेन्ट द्वारा खाता: ५५, ८४ एवं ७५ की भूमि का आपसी बँटवारा दिखाकर</p>	<p style="text-align: right;"></p>



अपीलार्थीगण/वादीगण की जमाबंदी संख्या: 17 एवं 104 की भूमि का दाखिल खारिज करा लिया गया तथा खाता: 55 खेसरा: 2932 का रकवा: 0.8.16 धूर भूमि पूर्णतः अपीलार्थीगण के दखल कब्जा एवं स्वामित्व में रही है उसे भी रेस्पोंडेन्ट्स अपने Schedule में रखकर दाखिल खारिज करा लिया। खाता संख्या: 75, खेसरा: 2828 का कुल रकवा: 0.4.18 धूर तथा जमाबंदी संख्या: 17 का कुल रकवा: 1.7.7 (एक बीघा सात कट्टा सात धूर) भूमि है। उक्त खाता खेसरा में से बिना किसी हक वो अधिकार एवं दखल कब्जा के कुल रकवा: 0.19.5 (उन्नीस कट्टा पाँच धूर) भूमि को निकाला जाना पूर्णतः अवैधानिक बतलाते है।

दूसरी ओर रेस्पोंडेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि प्रस्तुत वाद मौजा: हरियाही, अंतर्गत खाता संख्या: 84 एवं 85, खेसरा संख्या: 2618, 2621, 2641, 2642, 3152, 3237, 2441, 2781 एवं अन्य खेसरा का कुल रकवा: 06 बीघा 18 कट्टा 11 धूर 10 धूरकी भूमि तथा खाता संख्या: 75 एवं खेसरा संख्या: 2828, कुल रकवा: 9 कट्टा 16 धूर भूमि से संबंधित है।

रेस्पोंडेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी द्वारा उक्त वर्णित भूमि के संबंध में विपक्षी संख्या: 2 एवं 3 के नाम से कायम जमाबंदी खारिज करने हेतु दायर किया गया।

रेस्पोंडेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि उपरोक्त जमाबंदी से संबंधित आदेश अंचल अधिकारी द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या: 125/92-93 में दोनों पक्षों द्वारा दाखिल पंचनामा के तथ्यों के आधार पर दिनांक: 21.12.1992 को पारित किया गया।

रेस्पोंडेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि विवादी प्रश्नगत भूमि संयुक्त परिवार के पूर्वजों द्वारा खरिदगी से अर्जित है। पुराने खतियान का खाता संख्या: 55 के धारक उभय पक्ष दुल्हा मंडल, पुरन मंडल एवं ढोढाय मंडल सभी पिता स्व0 बुचनी मंडल थे और उन्हीं लोगों के नाम से भूतपूर्व जमीन्दार के समय से जमाबंदी संख्या 52 संचालित थी वो पुरन मंडल नावलद मर गये। अतएव उनके हिस्से की भूमि दुःखा मंडल एवं ढोढाय मंडल के बीच बंट गई।

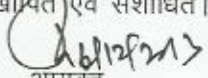
रेस्पोंडेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि संयुक्त परिवार में ही दुल्हा मंडल ने अपने पुत्र बुनी मंडल वो पौत्र सोने लाल मंडल वो भोही मंडल वो नन्द लाल मंडल के नाम से निबंधित दस्तावेज की तहरीरगी हुई जिसकी जमाबंदी संख्या: 17 बनाम बुनी मंडल वो जमाबंदी संख्या :104 बनाम बुनी मंडल हाल सोने लाल मंडल वो जमाबंदी संख्या 347 बनाम नंदलाल मंडल एवं जमाबंदी संख्या 194, 252 एवं 431 बनाम सोने लाल मंडल के नाम से कायम की गई तथा राजस्व रसीद निर्गत किया जाने लगा वो वर्ष 1949 में उभय पक्ष के पूर्वजों द्वारा 10.4.11 जमीन खरीद की गयी बतलाते हैं।

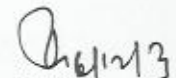
रेस्पोंडेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि वर्ष: 1992-93 में विभिन्न पंचों के समक्ष घरेलू पारिवारिक बँटवारा किया गया जिसके आधार पर अंचल अधिकारी, निर्मली के समक्ष जमाबंदी कायम करने हेतु आवेदन दिया गया तथा हल्का एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोंपरांत रत्तीलाल मंडल के नाम से 3 बीघा 11 कट्टा 4 धूर 5 धूरकी भूमि के निश्वत जमाबंदी संख्या: 1439 कायम हुआ तथा रामरूप मंडल के नाम से 3 बीघा 11 कट्टा 4 धूर 5 धूरकी भूमि के निश्वत जमाबंदी संख्या: 1440 कायम हुआ।

रेस्पोंडेन्ट के द्वारा अपने दावे के समर्थन में जमाबंदी वाद संख्या: 125/92-93 में दिनांक: 01.12.1992 को पारित आदेश की छायाप्रति, जमाबंदी संख्या: 1439 का मालगुजारी रसीद की छायाप्रति, जमाबंदी संख्या: 1440 का मालगुजारी रसीद की छायाप्रति एवं भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या: 42/2012 के आवेदन की छायाप्रति दाखिल किए हैं।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का सुक्ष्म अवलोकन किया पाया कि निम्न न्यायालय द्वारा मामले की

विस्तृत एवं सम्यक विवेचना करते हुए न्यायोचित आदेश पारित किया गया है। इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अस्तु अपील खारिज। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।
लेखायित एवं संशोधित।


आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा


आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा